

समामेलित कोलफील्ड्स लिमिटेड, और दूसरे

1961

10 फरवरी.

## THE JANAPADA SABHA, CHHINDWARA

(B. P. SINHA, C. J., S. K. DAS, A. K. SARKAR,  
K. C. DAS GUPTA and N. RAJAGOPALA AYYANGAR, JJ.)

कोयला कर-की वैधता-स्थानीय विधानमंडल स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस तरह के लेवी को अधिकृत करता है-विधायी क्षमता-केंद्रीय प्रांत स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1920 (1920 का सी.पी. 4), एस। 51—भारत सरकार अधिनियम, 1915 (5 और 6 जियो. 5, अध्याय 61), एस.एस. 80 ए(3), ओ। भारत अधिनियम, 1935 (26 जियो. 5, अध्याय 2), एस. 143-भारत का संविधान, कला. 227.

केंद्रीय प्रांत स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1920 की धारा 51, एक जिला परिषद को, स्थानीय सरकार की पिछली मंजूरी के अधीन, "एसएस 24, 48 में निर्दिष्ट के अलावा कोई भी कर, टोल या दर लगाने का अधिकार देती है।" 49, और 50।" 12 मार्च, 1935 को, उस क्षेत्र में कार्यरत एक स्वतंत्र खनन स्थानीय बोर्ड, जिसमें याचिकाकर्ता कुछ खदानों में काम कर रहे थे, और इसमें जिला परिषद की सभी शक्तियां निहित थीं, ने कोयला, कोयला-धूल पर कर लगाने का संकल्प लिया। और बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर खदानों में निर्मित या बेचा जाने वाला कोक। जिन याचिकाकर्ताओं को उनकी खदानों से कोयले के प्रेषण के लिए देय कर के रूप में कुछ धनराशि का भुगतान करने की मांग के नोटिस दिए गए थे, उन्होंने इस आधार पर कर लगाने की वैधता को चुनौती दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (1) भी शामिल है। अधिनियम जो एस द्वारा. 51 कर लगाने को अधिकृत करता है, गवर्नर-जनरल की पूर्व मंजूरी के बिना स्थानीय विधायिका द्वारा पारित किया गया था, जिससे एस का उल्लंघन हुआ। भारत सरकार अधिनियम, 1915 का 80 ए(3), और भले ही यह पौया गया हो कि यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने से पहले वैध रूप से पारित किया गया था, जिसने एस पेश किया था। 1915 के अधिनियम में 80 ए द्वारा प्रदत्त शक्ति एस। कर लगाने के लिए 51 का प्रयोग केवल 1935 में किया गया था और उस तारीख तक। 80 ए को भारत सरकार अधिनियम, 1915 में पेश किया गया था, और उसके बाद गवर्नर-जनरल की पूर्व मंजूरी

## रिपोर्टें

प्राप्त किए बिना कोई कानूनी कर नहीं लगाया जा सकता था, (2) यानी। केंद्रीय प्रांत स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1920 के 51, इसकी भाषा पर और - उस अनुभाग में संदर्भित अन्य प्रावधानों के संदर्भ में, कोयला कर की प्रकृति के कर लगाने को अधिकृत नहीं करता है, और (3) कि, किसी भी स्थिति में, कर आने के बाद कानूनी रूप से लगाया जाना बद हो जाएगा

961 यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 और भारत के संविधान के प्रभाव में है, क्योंकि इस तरह के कर का एकीकरण केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है।

कोलफील्ड्स लिमिटेड ने माना: (1) कि मध्य प्रांत स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1920, गवर्नर-जनरल की सहमति प्राप्त करने के बाद,

Chhimdwava एस के परंतक में. 80 ए(3) और एस. भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 84(2)।

(2) केंद्रीय प्रांत स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1920 की वैधता, जब अधिनियमित हुई, भारत सरकार अधिनियम, 1915 के तहत किसी भी आपत्ति के लिए खुली नहीं थी, बाद के अधिनियम में कोई भी संशोधन किसी भी तरह से इसकी निरंतर वैधता को प्रभावित नहीं कर सकता था और संचालन।

(3) कि स के उचित निर्माण पर। 1920 के अधिनियम के 51, कोयला कर की वसूली को स्थानीय प्राधिकरण के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है।

(4) कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 और भारत के संविधान के लागू होने के बाद भी प्रश्नगत कर की निरंतर वसूली, एस के मददैनजर वैध है। 1935 के अधिनियम के 143 और कला। संविधान के 227.

मूल क्षेत्राधिकार: 1959 की याचिका संख्या 31।

कला के तहत याचिका. भारत के संविधान की धारा 32, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए।

एम. सी. सीतलवाड़े, भारत के अटॉर्नी-जनरल, एस. एन.

याचिकाकर्ताओं की ओर से एंडी, जे.बी. दादाचंजी, रामेश्वर नाथ और पी.एल. वोहरा।

प्रतिवादी की ओर से बी. सेन और आई. एन. श्रॉफ।

1961. फरवरी 10. न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

Ayy,angar J. AYYANGAR, J.—कला के तहत यह याचिका. 32 है जनपद सभा, सविङ्ग खण्डों के दृष्टिगत इसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती याचिकाकर्ताओं को दी गई दो 410 टी की वैधता पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्हें प्रतिवादी द्वारा "कोयला कर" के रूप में वर्णित राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, जो कि केंद्रीय प्रांत और बरार स्थानीय सरकार अधिनियम के तहत गठित एक स्थानीय बोर्ड है। 1948 (सी.पी. और बरार अधिनियम 1948), चुनौती का आधार यह है कि कर लगाने के लिए कोई विधायी शक्ति नहीं थी और परिणामस्वरूप कला के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार थे। 19(1)(एफ) एवं (जी) का उल्लंघन किया जा रहा है।

शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि अब लगाया गया कर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लगाया गया है

12 मार्च 1935 से और वह पहला अवसर जब

196

इसकी वैधता पर हमला केवल 1957 में हुआ था, हालाँकि यदि

याचिकाकर्ता अपनी दलीलों में सही हैं कि उनकी सहमति <sup>एकीकृत</sup> कोलफील्ड्स लिमिटेड स्वयं इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है

उन्हें राहत. हालाँकि, इससे पहले हमने बिंदु निर्धारित किए थे

सभा,

छिंदौरा याचिका के समर्थन में विद्वान अटॉर्नी-जनरल द्वारा आग्रह किया गया, यदि हम इस कर के लगाए जाने के इतिहास को संक्षेप में बताएं तो यह सुविधाजनक होगा। अय्यंगार जे .

मध्य प्रांत स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1920 (1920 का सी.पी. अधिनियम IV) की धारा 51, जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा, इस प्रकार है:

"51(1)। फिलहाल लागू किसी भी कानून या अधिनियम के प्रावधान के अधीन, एक जिला परिषद, बलाई गई एक विशेष बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा इस प्रयोजन के लिए, धारा 24, 48, 49 और 50 में निर्दिष्ट के अलावा कोई भी कर, टोल या दर लगाएँ।

(2). उप-धारा (एल) के तहत किसी भी कर, टोल या दर को पहली बार लगाना स्थानीय सरकार की पिछली मंजूरी के अधीन होगा।"

याचिकाकर्ता छिंदवाड़ा जिले में स्थित कुछ खदानों पर काम कर रहे हैं और खदानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए 1926 में या उसके आसपास एक स्वतंत्र खनन स्थानीय बोर्ड का गठन किया गया था और ऐसे बोर्ड अधिनियम के तहत स्थानीय बोर्ड की परिभाषा में शामिल हैं और उन्हें निहित किया गया है उनमें जिला परिषद की सभी शक्तियाँ होती हैं। इस खनन बोर्ड ने, स्थानीय सरकार की पिछली मंजूरी प्राप्त करने के बाद, 12 मार्च, 1935 को एस के तहत अपेक्षित बहुमत से पारित किया। अधिनियम के 51(1) में कोयला, कोयला-धूल और कोक पर निम्नलिखित शर्तों में कर लगाने का प्रस्ताव है:

"कर तीन पाई, प्रति टन सीएन कोयला, कोयला धूल या कोक की दर से लगाया जाएगा, जो खदानों में निर्मित, रेल द्वारा निर्यात के लिए बेचा जाता है या स्वतंत्र खनन स्थानीय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर रेल द्वारा

निर्यात के अलावा अन्यथा बेचा जाता है। तख्ता।" तब से कर लगाया और वसला जाता रहा है।

1920 के स्थानीय-स्वशासन अधिनियम को केंद्रीय प्रांत और बरार स्थानीय सरकार अधिनियम, 1948 द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित किया गया था, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बाद के अधिनियम और बाद में किए गए कुछ संशोधनों में स्थानीय की निरंतरता के प्रावधान शामिल हैं। कोलफील्ड्स लिमिटेड के तहत गठित बोर्ड

निरस्त अधिनियम और जारी रहने के लिए-

जनपद सब्बा, 1948 के अधिनियम के प्रारंभ में छीमदवापा की तिथि पर लागू करों और उपकरणों की शक्ति। प्रतिवादी, जैसा कि पहले कहा गया था, 1948 के अधिनियम अय्यंगार जे के तहत गठित किया गया था और माना जाता है कि वह स्वतंत्र का उत्तराधिकारी है। खनन बोर्ड, जिसने 12 मार्च 1935 के अपने संकल्प द्वारा कर लगाया था, और यदि मूल अधिरोपण वैध था, तो कानूनी तौर पर वह कर जारी रखने का हकदार है। इस स्तर पर उल्लेख करने के लिए केवल एक अन्य मामला है, अर्थात्, शल्क की दर, जैसा कि पहले निकाले गए संकल्प से देखा गया था, 1935 में लगाए जाने पर 3 पाई प्रति टन थी, जिसे स्थानीय निकाय द्वारा बढ़ाकर 9 पाई प्रति टन कर दिया गया था। 1949 में टन, यही वह दर है जो अब प्रचलित है। 23 अगस्त, 1958 को, प्रतिवादी-सभा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पहले और दूसरे याचिकाकर्ताओं को मांग के दो नोटिस दिए, जिसमें उनसे रुपये को भगतान करने की मांग की गई। 21,898.64 और रु. 1 जनवरी, 1958 से 30 जून, 1958 की अवधि के लिए उनकी संबंधित खदानों से कोयले के प्रेषण के लिए क्रमशः प्रत्येक द्वारा देय कर के रूप में। यह इन नोटिसों की वैधता है जो इस पेटी में लगाई गई हैं। tion.

विद्वान अटॉर्नी-जनरल की दलीलें तीन थीं:

(एले) स्वतंत्र खनन बोर्ड द्वारा कर की वसूली 1935 में इसके मूल लगाए जाने की तिथि पर अमान्य थी, और परिणामस्वरूप प्रतिवादी सा, भा - इसके उत्तराधिकारी - को खेल जारी रखने का कोई अधिकार नहीं मिला।

(2) यह मानते हुए कि लेवी मूल रूप से लगाए जाने पर वैध थी, पहले भारत सरकार अधिनियम, 1935 और बाद में 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद यह कानूनी नहीं रह गई, जिसके तहत प्रश्न में कर या कुछ हिस्से यह विशेष रूप से केंद्र या केंद्र सरकार द्वारा

लगाया जाने योग्य हो गया और पहले से मौजूद करों की बचत से कवर नहीं किया जाएगा। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के 143, और उसके बाद कला के संविधान के 277.

(3) आगे यह मानते हुए कि भारत सरकार अधिनियम के 8.143 में निहित प्रावधान कर, इसके द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा या कोलफील्ड्स ए गामाटेड लिमिटेड की निरंतरता को कवर करता है। जिसके लिए यह

भारत सरकार अधिनियम (अप्रैल 1, 1937), और 1949 में  
दर में 9 पाई प्रति टन की वृद्धि हुई और या तो पूरी तरह से  
या कम से कम

Chkindwapæ

Ayyangar J•

प्रावधान किया गया है, वह केवल एक, की दर से कर के लिए है  
3 ./अनापाड़ा सभा के शुरू होने से पहले प्रचलित पाई प्रति टन,  
लेवी की मांग कम से कम आंशिक रूप  
से अवैध है।

अब हम इन बिंदुओं पर उसी क्रम में विचार करने के लिए  
आगे बढ़ेंगे:

(1) कि 12 मार्च 1935 के संकल्प द्वारा स्वतंत्र खनन  
बोर्ड द्वारा कर लगाया जाना अमान्य था। इसे तीन  
अलग-अलग आधारों पर आराम देने की मांग की गई  
थी:

(ए) कि कर का लेव एस के उल्लंघन में था।  
भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 80 ए(3)।  
केवल भाग को उद्धृत करने के लिए धारा 80 ए(3)  
अधिनियमित की गई-

"किसी भी प्रांत की स्थानीय विधायिका, गवर्नर  
जनरल की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई कानून नहीं बना  
सकती है या उस पर विचार नहीं कर सकती है - (ए) किसी  
भी नए कर को लगाने या लगाने के लिए अधिकृत करना  
जब तक कि कर एक, कर से छूट के रूप में निर्धारित न हो  
इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा यह  
प्रावधान; या

अब लगाए गए कर अनुसूचित कर नियमों की सूची में  
शामिल नहीं हैं और इसलिए कर लगाने को अधिकृत करने  
वाले विधेयक पर विचार करने से पहले गवर्नर जनरल की  
पिछली मंजूरी की आवश्यकता थी। और भे अधिनियम जो  
एस द्वारा 51 कर लगाने को अधिकृत करता है, जिसे  
सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना स्थानीय विधायिका  
द्वारा पारित किया गया था।

## 10 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टें [1962]

एकीकृत

इस विवाद को स्थापित करते हुए दायर की गई याचिका प्रो. इस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद पारित किया गया था, जिसके द्वारा एस. 1915 के अधिनियम में 80A लागू किया गया। यदि वह सही स्थिति होती, तो परंतुक

एस। 80 ए (3) पढ़ना:

"बशर्ते कि कोई अधिनियम या किसी अधिनियम का प्रावधान स्थानीय विधायिका द्वारा बनाया गया हो, और सहमति-

कोलफील्ड्स लिमिटेड

इसके अनुसरण में गवर्नर-जनरल द्वारा संपादित

अधिनियम, केवल कारण से अवैध नहीं माना जाएगा

जनपद सभा,

इसके लिए राज्यपाल की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है-

छिंदवाड़ा

इस अधिनियम के तहत सामान्य।"

उपरोक्त आपत्ति का पूर्ण उत्तर होगा, अय्या-नगर जे. चूंकि भारत सरकार अधिनियम, 1915 के तहत, 1919 में इसके संशोधन से पहले और बाद में, प्रत्येक विधेयक, राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के बाद, स्थानीय विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। , गवर्नर-जनरल को प्रेषित किया जाना था और गवर्नर द्वारा अपनी सहमति देने के बाद ही कानून बन सकता था (अधिनियम की धारा 81(1) और (3) देखें)। गवर्नर-जनरल ने इस प्रावधान के तहत अधिनियम को सहमति दे दी थी, यह कभी भी विवाद में नहीं था। परंतुक में निहित बचत, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसमें निहित सामान्य बचत के अतिरिक्त है। भारत सरकार अधिनियम की धारा 84(2) (केवल भौतिक शब्दों को पढ़ने के लिए): "...किसी भी स्थानीय विधायिका के किसी भी

अधिनियम की वैधता इस आधार पर किसी भी कानूनी कार्यवाही में सवाल उठाने के लिए खली नहीं होगी कि अधिनियम प्रभावित करता है... एक केंद्रीय विषय" जो व्यापक महत्व का है और अब विधायी क्षमता के सभी प्रश्नों को न्यायालयों के दायरे से हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हालाँकि, बहस के चरण में, यह पाया गया कि अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने से पहले ही कानून बन गया था, जिसके परिणामस्वरूप याचिका में उठाए गए विवाद एस पर आधारित थे। 80 ए(3) का आग्रह नहीं किया जा सका। अधिनियम की शुरुआत में किए गए पाठों से, यह पाया गया कि धारा के तहत स्थानीय विधानमंडल में उपाय पेश करने के लिए गवर्नर-जनरल की पिछली मंजूरी प्राप्त कर ली गई थी। भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 79(2)-अर्थात्, धारा से पहले। भारत सरकार अधिनियम, 1919 में धारा 80 ए(3) को लागू किया गया।

इसलिए, विद्वान अटॉर्नी-जनरल ने अपने तर्क को संशोधित किया और आईबी को इस रूप में प्रस्तुत किया: इसमें कोई संदेह नहीं है जब एस। अधिनियम का 51 अधिनियमित किया गया था, यह स्थानीय विधानमंडल की क्षमता के भीतर था। लेकिन कर लगाने के लिए उस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग केवल 1935 में और उस तारीख तक किया गया था। 80 ए को भारत सरकार अधिनियम और वहां पेश किया गया था।

गवर्नर-जनरल की पूर्व मंजूरी के बिना कोलफील्ड्स लिमिटेड को अनुसूचित कर नियमों में शामिल करने के बाद कोई कर नहीं लगाया जा सकता था, इसके बाद अमल में आ गया।

कलंकित हम इस तर्क पर बिना किसी बल के पूर्णतः विचार करते हैं। एस की वैधता अधिनियम का 51, अधिनियमित होने पर, भारत सरकार अधिनियम, 1915 के तहत किसी भी आपत्ति के लिए खुला नहीं होने के कारण, किए गए संशोधन

छिंदवाड़ा

अय्यंगर जे.

भारत सरकार अधिनियम, 1915, 1919 के अधिनियम द्वारा, किसी भी तरीके से, या किसी भी हद तक, स्पष्ट रूप से या यहां तक कि निहितार्थ से भी उस धारा की निरंतर वैधता और संचालन को प्रभावित या

## 10 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टें [1962]

### एकीकृत

खर्च नहीं करता है। जाहिर है, एस. 80 ए(3) का संबंध केवल उस प्रावधान के लागू होने के बाद कानून बनाने के लिए प्रारंभिक बातें निर्धारित करने से था और एक बार कानून बनने और लागू होने के बाद, बिलों को आकर्षित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का कोई सवाल ही नहीं है। इसके अलावा, सभी विवादों पर विराम लग गया है और अब जिस प्रकार का तर्क दिया गया है, उसे आर द्वारा खारिज कर दिया गया है। अनुसूचित कर नियमों में से 5 जो चलते हैं:

"इन नियमों में कुछ भी स्थानीय प्राधिकारी के पूर्व मंजूरी के बिना या स्थानीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ कर लगाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जब ऐसा अधिकार उसे किसी भी समय लागू कानून द्वारा प्रदान किया गया हो।"

अतः प्रस्तुतीकरण यह है कि एस द्वारा प्रदत्त शक्ति से पहले। अधिनियम के 51 में, गवर्नर-जनरल की पिछली मंजूरी प्राप्त की जानी थी या नया कानून होना चाहिए, इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

(b) इस शीर्षक के तहत आग्रह किया गया दूसरा मामला एस के शुरुआती शब्दों को दिए जाने वाले अर्थ पर आधारित था। अधिनियम का 51: "तत्समय लागू किसी कानून या अधिनियम के प्रावधान के अधीन"। यह सुझाव दिया गया था कि प्रावधान एस में निहित है। भारत सरकार अधिनियम की धारा 80 ए(3) उस धारा के तहत बनाए गए अनुसूचित कर नियमों के साथ पढ़ी गई, जो "तत्काल लागू एक कानून" का गठन करती है, जिसके अधीन कर लगाने की शक्ति थी। पहली जगह में, यह स्पष्ट है कि एक ला, जैसा कि एस में पाया जाता है। स्थानीय विधानमंडल के भविष्य के अधिनियमों को अधिनियमित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाली धारा 80 ए(3) को शब्दों के भीतर नहीं समझा जा सका। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी, तो आर के सामने। अनुसूचित कर नियमों में से 3, कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा सुझाए गए निर्माण का कोई आधार नहीं हो सकता है।

(c) विवाद करने का आखिरी कारण बताया गया जनाज़ा सभा, कर लगाने की मूल वैधता, वह थी

छिंदवाड़ा

एस। अधिनियम की धारा 51 इसकी भाषा पर और उस धारा में संदर्भित अन्य प्रावधानों के संदर्भ में, "कोयला कर" की प्रकृति के कर या उपकर लगाने को अधिकृत नहीं करती है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में पूर्णतः असमर्थ हैं। एस के प्रासंगिक शब्द. 51 हैं:

अय्यंगव जे •

"धारा 24, 48, 49 और 50 में निर्दिष्ट के अलावा कोई भी कर, टोल या दर लगाए"।

यह सुझाव नहीं दिया गया है कि "कोयला कर" निर्धारित किसी भी धारा में निर्दिष्ट है, और इसलिए उस सहित कोई अन्य कर लगाने की शक्ति थी जो अब लागू है। विद्वान महान्यायवादी कैसे। कभी सुझाव दिया कि एस द्वारा अधिकृत कर. 51 अभी भी कुछ हद तक अन्य अनुभागों में उल्लिखित करों के समान होना चाहिए, हालाँकि उनके समान नहीं हैं। जाहिर है, "उनके अलावा..." शब्दों के सामने एजस्ट्रेम जेनेरिस का नियम विरोधाभासी है और यदि ऐसा है तो निर्माण का कोई भी नियम "कोयला कर" को स्थानीय प्राधिकरण के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, हम मानते हैं कि 1935 में लगाया गया कर मूल रूप से वैध था।

(2) अगला सवाल यह है कि क्या टैक्स लेना बंद हो गया है? भारत सरकार अधिनियम, 1935 और संविधान के लागू होने के कारण कितना शुल्क लगाया जा सकता है? इन दोनों संवैधानिक अधिनियमों में ऐसे स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं जिनके तहत कर, उपकर आदि, जो पहले स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्रों के प्रयोजनों के लिए कानूनी रूप से लगाए गए थे, एकत्र किए जा सकते हैं और उन्हीं उद्देश्यों के लिए लागू किए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे कर उसके बाद केवल केंद्र या संघ सरकार द्वारा ही लागू जा सकते हैं, जैसा भी मामला हो (भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 143 और संविधान की धारा 277 के तहत)। इसलिए यह आपत्ति कि "कोयला कर" या इसके कुछ घटक, केवल केंद्र सरकार या केंद्र

## 10 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टें [1962]

एकीकृत

सरकार द्वारा लगाए जा सकते थे, कर की निरंतर वैधता और अनिवार्यता पर सवाल उठाने का कोई आधार नहीं है। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कर प्रांतीय या राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेवी एस के तहत मान्य होगी। भारत सरकार सेमामेलन अधिनियम और कला की धारा 292। संविधान के 372 एस में विशेष प्रावधान की सहायता के बिना भी कोलफील्ड्स लिमिटेड. 143 या कला। 277. इन विचारों को ध्यान में रखते हुए विद्वान जनपद सभा, इस छिदवाड़ा पर अटॉर्नी जनरल ने हमें गंभीरता से संबोधित नहीं किया

बिंदु।

Ayyangay J.

(3) आग्रह किया गया अंतिम बिंदु 1949 में, यानी, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रारंभ के बाद, कर की दर में 9 पाई प्रति टन की वृद्धि की वैधता के संबंध में था। इस आपत्ति का संकेत भी नहीं दिया गया था। याचिका अब हमारे सामने है, और हमने याचिकाकर्ताओं को मुद्दा उठाने की अनुमति देना उचित नहीं समझा।

नतीजा यह होता है कि याचिका विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज.

मुख्य खान निरीक्षक एवं

एक और

10 फरवरी.

LALA KARAM CHAND THAPAR ETC.

(बी.पी. एस.एन.रा., सी.जे., एस.के. दास, के.सी. दास गुप्ता,

# 1 एस.सी.आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 11

N. RAJAGOPALA AYYANGAR and J. R.  
MUDHOLKAR, JJ.)

कोलियरी कंपनी-कोयला खदानों का वि०१ एशन  
कंपनी के सभी निदेशकों, प्रबंध एजेंटों और कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ  
मकदमा - वैधानिकता - 1923 के खान अधिनियम को निरस्त किया गया और  
फिर से लागू किया गया - इसके तहत बनाए गए विनियम, यदि लागू रहते हैं -  
'निदेशकों में से कोई भी' का अर्थ है - भारतीय कोयला खान विनियम, 1926—  
खान अधिनियम, 1923 (1923 का 4), धारा. अधिनियम, 1952, (1952 का 35),  
एस.एस. 2(1), 76-जेनर्ड क्लॉजेज एक्ट, 1897 (1897 का 10), एस. 24—भारत  
का संविधान, कला. 20(1).

एक कंपनी के निदेशक, जो एक कोलियरी का मालिक था, कंपनी  
के प्रबंध एजेंटों के निदेशक, और प्रबंधक और कोलियरी के एजेंट पर  
एसएस के तहत अपराध के लिए मकदमा चलाया गया था। उल्लंघन के  
लिए खान अधिनियम\* 1952 की धारा 73 एवं 74

Shivank Singh  
J.M.Aligarh